RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 134
दि. 13.09.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति ने श्री सी. पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ दिलाई

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (12 सितंबर, 2025) राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री सी. पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ दिलाई।

प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के रूप में थिरु सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में थिरु सी.पी. राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।

श्री मोदी ने श्री राधाकृष्णन को जनता की सेवा के लिए समर्पित एक सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

एक्स पर अपनी एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहाः

"श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहा। एक समर्पित लोक सेवक के रूप में, उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित कर दिया। जनता की सेवा के लिए समर्पित, उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना करता हूं।"

नेपाल में सुशील कार्की बनीं पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। GenZ युवाओं की बगावत ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो तूफान खड़ा किया, उसके बाद अब सत्ता की कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथों में आ चुकी है। 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने शुक्रवार (12 सितंबर 2025) को सुशीला कार्की को पहली महिला कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया। यह जानकारी काठमांडू पोस्ट ने पुष्ट की है।

शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को गोपनीयता की शपथ दिलाई। सरकार को छह महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले रेस में काठमांडू के मेयर बालेन शाह और कुलमन घीसिंग नाम भी उभर कर सामने आए थे, लेकिन सुशीला ने सभी को पीछे छोड़ दिया। अब ऐसे में सभी के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि सुशीला कार्की किस जाति से ताल्लुख रखती हैं? आइए जानते हैं....

8 सितंबर 2025 को काठमांडू के मैतीघर मंडला में शुरू हुए प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। युवाओं ने संसद भवन पर हमला किया, आगजनी की, और नेताओं के घरों को निशाना बनाया। 19 मौतें 8 सितंबर 2025 को हुई, और 9 सितंबर को 15 और जुड़ गईं – कुल 34 मौतें। 300 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें छात्र, पत्रकार, और पुलिसकर्मी शामिल हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, नेशनल ट्रॉमा सेंटर में 8, एवरेस्ट हॉस्पिटल में 3, और सिविल हॉस्पिटल में 3 मौतें हुईं।

ओली सरकार ने बैन हटाया, लेकिन देर हो चुकी थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के 21 सांसदों और 4 मंत्रियों (रमेश लेखक, राम नाथ अधिकारी, प्रदीप पौडेल, प्रदीप यादव) के इस्तीफे ने सरकार को ढहा दिया। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने ओली से इस्तीफा मांगा। ओली ने दुबई भागने की कोशिश की, लेकिन सेना ने रोका। अब, जेन-जेड युवाओं ने सुशीला कार्की को अंतरिम PM चुना – Discord पर वोटिंग से नाम तय हुआ। सुशीला ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

भारत की हर गली खेल का मैदान होनी चाहिए, हर मंच पर भारत का झंडा लहराना चाहिएः डॉ. मनसुख मांडविया

(जीएनएस)।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने देश के हर घर में खेल संस्कृति को शामिल करने और प्रत्येक बच्चे में खेल के प्रति उत्साह एवं जुनून पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "भारत की हर गली खेल का मैदान बननी चाहिए और हर मंच पर भारत का झंडा लहराना चाहिए।" केन्द्रीय मंत्री ने भारतीय संदर्भ में खेलों की जीवंत और बहुआयामी प्रकृति उल्लेख करते हुए कहा, "खेल जीवन जीने का एक तरीका है; यह हमारी प्रकृति और संस्कृति का हिस्सा है, और यह उसी तरह हैं जैसे यह एक पेशा, मनोरंजन का एक रूप और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है।"

डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में स्पोर्टस्टार एक्स केपीएमजी प्लेकॉम बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स समिट 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए खेलों को एक जन आंदोलन बनाने की

आवश्यकता पर जोर दिया ताकि प्रत्येक नागरिक इनके साथ जुड़े। उन्होंने "संडे ऑन साइकिल्स" जैसी पहल को जमीनी स्तर पर जुड़ाव का प्रतीक बताया और हर घर में खेल संस्कृति को शामिल करने का आह्वान किया।

डॉ. मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के खेल जगत में हुए सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने "फिट इंडिया" और "खेलो इंडिया" जैसी पहलों के महत्व को दोहराते हुए कहा कि इनसे नागरिकों में जागरूकता और उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने कहा, "खेलों में हमारे सुधार निरंतर जारी रहने चाहिए। देश में असीमित प्रतिभाएं हैं। उन्हें अवसर, प्रोत्साहन और सम्मान की आवश्यकता है।"

केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में भारत को दुनिया के शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाने के लिए एक साहसिक और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

पटना में एपीडा के पहले कार्यालय का उद्घाटन

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बिहार को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के केंद्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 11 सितंबर, 2025 को पटना, बिहार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा के साथ-साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, एपीडा नेतृत्व, उद्यमी, एफपीओ और किसान समूह भी उपस्थित थे।

आज के बदलते समय में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान एवं विकास संस्थान-अकादमिक सहयोग काफी महत्वपूर्ण हैः रक्षा सचिव

(जीएनएस)।

रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने आज के लगातार परिवर्तित होते समय में सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक एवं निजी उद्योग, डीआरडीओ जैसे अनुसंधान संस्थानों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। रक्षा सचिव 12 सितंबर, 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित ह्यप्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का तालमेलह्ल विषय पर उद्घाटन सत्र स्ट्राइड 2025 सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रौद्योगिकी व्यवधान न केवल युद्ध की प्रकृति को बदल रहा है, बल्कि रक्षा उद्योग के व्यवसाय को भी परिवर्तित कर रहा है, उन्होंने सभी हितधारकों से नवीनतम तकनीकी रुझानों से अवगत रहने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

रक्षा सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी श्रेष्ठता एवं औद्योगिक सामर्थ्य अक्सर युद्ध के परिणाम को निर्धारित करते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता व्यक्त है कि रक्षा उद्योग हमारे विनिर्माण क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ गति से बढ़े ताकि विकसित भारत तथा वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन नवाचार के क्षेत्र में एक विकसित राष्ट्र बनने, भारत की स्टार्टअप संस्कृति को विस्तार देने, हमारे औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने व रोजगार सृजन तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग से होने वाले लाभों के व्यापक मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण है।

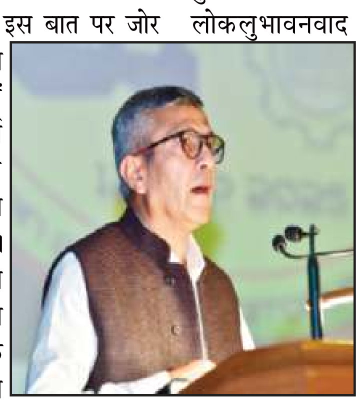

राजेश कुमार सिंह ने बताया कि चल रहे संघर्षों के परिणामस्वरूप दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद एवं आर्थिक संरक्षणवाद को बढ़ावा मिला है और साथ ही आर्थिक विखंडन, बाहुपक्षीय संस्थाओं का पतन तथा राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर भी देखी गई है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, "हमें अपनी सॉफ्ट पावर को सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि हार्ड पावर अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।"

रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश तकनीकी दौड़ में आगे रहे। इन उपायों में रक्षा खरीद मैनुअल 2009 और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन करना शामिल है ताकि उन्हें अधिक गतिशील, सक्रिय, कम प्रक्रिया-भारी तथा परिणाम पर अधिक केंद्रित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करने, जमीनी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

इसका उद्देश्य भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को व्यापक और विविध बनाना है।

राजेश कुमार सिंह ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने में निजी उद्योग की भूमिका की सराहना करते हुए उनसे अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण क्षमता में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में तब तक उस स्तर का नवाचार और क्षमता नहीं आ सकते हैं, जिसकी सशस्त्र सेनाओं को आवश्यकता है, जब तक कि निजी क्षेत्र में आगे रहने तथा निवेश करने की इच्छाशक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आपको छिटपुट आधार पर ऑर्डर मिलते हैं। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यदि हमारे पास प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग की ताकत है, तो हम घरेलू तथा निर्यात ऑर्डर के संयोजन के माध्यम से खुद को बनाए रखने में सक्षम होंगे।

भारतीय नौसेना की क्विज प्रतियोगिता-थिंक (टीएचआईएनक्यू) 2025 को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली

भारतीय नौसेना की राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता, थिंक 2025 के लिए देशभर से 35,470 टीमों ने पंजीकरण कराया है।

यह क्विज प्रतियोगिता कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों, युवाओं और भविष्य की अग्रणी प्रतिभाओं को भारतीय नौसेना को जानने का एक रोमांचक अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

इस क्विज प्रतियोगिता की शुरूआत 10 जून 2025 को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ हुई। देश भर के छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों ने इस क्विज प्रतियोगिता के प्रति गहरी रुचि और उत्साह दिखाया है। इस क्विज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एलिमिनेशन राउंड में स्कूल एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे।

निफ्ट पटना में स्वयं सहायता समूह जीविका की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

(जीएनएस)।

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) पटना ने आज केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उद्योग कौशल प्रदान कर बिहार के बढ़ते वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाना है, ताकि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।

श्री गिरिराज सिंह ने साझेदारी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि निफ्ट पटना ने बेगूसराय में जीविका दीदियों के लिए पहले ही कई सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिससे उनके सिलाई कौशल और आय क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से निफ्ट विस्तार केंद्र में प्रशिक्षित जीविका दीदियों को अब एबीएफआरएल कारखाने में नौकरियां

मिल पाएगी। शुरू में, आसपास के क्षेत्र की 3.5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा और भविष्य में, निकटवर्ती जिलों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन सहयोग के तहत, जीविका दीदियों के नाम से पहचाने जाने वाली स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को निफ्ट पटना में परिधान निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और मशीनरी संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को बेगूसराय जिले में आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) की आगामी वस्त्र निर्माण इकाई में रोजगार देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे इन महिलाओं के कौशल विकास से लेकर सुरक्षित आजीविका तक का सुव्यवस्थित मार्ग तैयार होगा।

उत्साह, समावेश और सशक्तिकरण के प्रतीक पर्पल फेस्ट 2025 का समापन

(जीएनएस)।

पर्पल फेस्ट 2025 एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा में 1,800 से अधिक पंजीकृत आगंतुकों की बड़ी भागीदारी के साथ 11 सितंबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उप महानिदेशक सुश्री ऋचा शंकर ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए, समाज में समावेशिता को प्रोत्साहन देने, दिव्यांगजनों को समुदाय के समान सदस्य के रूप में स्वीकार करने, स्कूलों में समावेशिता सुनिश्चित करने, बधिर व्यक्तियों के संघर्षों और उपलब्धियों की सराहना करने और पर्पल फेस्ट के माध्यम से प्रदर्शित समावेशिता का उत्सव मनाने के महत्व पर जोर दिया।

इस सत्र में एमिटी विश्वविद्यालय की डॉ. जयंती पुजारी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुति तथा एमिटी विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव बंसल ने बताया कि पर्पल फेस्ट के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए हैं।

सांस्कृतिक और खेलकूद के अनेक कार्यक्रमों के साथ कार्यक्रम का अंतिम दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहा। खेल खंड के अंतर्गत, इनडोर और आउटडोर रुप से पाँच प्रमुख खेल - क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ इसमें भागीदारी करी जिससे ये प्रतिस्पर्धा जीवंत और आकर्षक बन गई। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण समावेशी क्रिकेट मैच था, जिसमें एमिटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने आईएसएलआरटीसी के बधिर छात्रों के साथ मुकाबला किया, जिससे समावेशिता और सौहार्द की सच्ची भावना का प्रदर्शन हुआ।

अमर ज्योति, अक्षय प्रतिष्ठान, एनआईईपीआईडी, और एवाईजेएनआईएसएचडी नोएडा जैसे विशेष स्कूल और संस्थान भी इस महोत्सव में शामिल हुए, जिससे यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन करने के लिए एक विविध मंच बन गया।

इस अवसर पर एक सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पर्पल फेस्ट में 22 उद्यमिता स्टॉल भी आयोजित किए गए, जिनमें अमर ज्योति, डीएफडीडब्ल्यू और आर्ट बाय हार्ट जैसे संगठन और समूह शामिल थे। इन स्टॉलों को लोगों से अपार समर्थन मिला, जिससे दिव्यांगजन उद्यमियों को दृश्यता और वित्तीय सशक्तिकरण का लाभ मिला । इसके अतिरिक्त, आईएसएलआरटीसी स्टॉल पर एनबीटी द्वारा 200 सुलभ " वीरगाथा" पुस्तकें वितरित की गईं, जिससे समुदाय के लिए सुलभ संसाधन सुनिश्चित हुए।

श्री एसके श्रीवास्तव ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। आईएसएलआरटीसी के निदेशक श्री कुमार राजू ने समापन संबोधन देते हुए आयोजक दलों के प्रयासों और सभी भाग लेने वाले लोगों के उत्साह की

सम्पादकीय

सोशल मीडिया और सरकारी दबाव

ऐसा नहीं है कि नेपाल में जन आंदोलन पहली बार हो रहा है। ऐसे जन आंदोलन पहले भी कई बार हुए हैं। पर जिस प्रकार से इस बार इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप लिया है वह अभूतपूर्व है। नेपाल में मौजूदा विरोध-प्रदर्शनों में शामिल अधिकांश युवा 28 वर्ष से कम हैं, इसलिए इसे जेन जी का आंदोलन कहा जा रहा है। यह पहला मौका है जब युवा पीढ़ी इस तरह से सड़क पर उतरी। लेकिन क्या इतनी नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी की लेकर है? इसके जवाब में यही कहा जा सकता है.. शायद नहीं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतरने से पहले युवा लोग सत्ताधारी वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार और नेपो बेबीज को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे थे। उनके लिए सोशल मीडिया अपनी नाराजगी जाहिर करने का एक हथियार बन चुका था। लोग प्रमुख परिवारों के युवा सदस्यों की तस्वीरें पोस्ट करके सवाल उठा रहे थे।

उनकी जीवन शैली का खर्च वैसे उठाया जाता है? सोशल प्रतिबंध युवाओं के लिए अपना हथियार छीनने जैसा भी था। बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। सोशल मीडिया पर नेताओं के भ्रष्टाचार और उनके बच्चों की ऐशो-आराम वाली जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। सांसद परिसर तक पहुंचे युवाओं ने नारे लगाए कि हमारा टैक्स तुम्हारी रईसी कि नहीं चलेगी। सोशल मीडिया बैन ने बस उस आग में घी डालने का काम किया। जिसके पीछे लंबे समय से जमा हताशा और आक्रोश का फल था। जिस प्रकार से इस आंदोलन ने शक्ल ली है उससे तो हमारा मानना है कि यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं यह तो पूरी व्यवस्था का सिस्टम बदलने के आंदोलन का रूप ले चुका है।

पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमे कभी भी इस तरह की आगजनी, तोड़फोड़, बदले की भावना से हत्याएं संसद, सरकारी इमारतें जलाना पहले कभी नहीं देखा गया। उनके निशाने पर नेता हैं चाहे वे किसी भी दल के हों। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस उक्त आंदोलन के पीछे केवल घरेलू असंतोष है या फिर कुछ विदेशी ताकतों ने भी इसे हवा देने की कोशिश है। कहीं नेपाल के बहाने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का खेल तो नहीं खेला जा रहा? कुछ छात्रों ने भी दावा किया कि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय था पर इसे बाहरी तत्वों ने हाईजैक कर लिया और हिंसा का तांडव मचा दिया। सूदन गुरुंग जिस सामाजिक संगठन हामी (हामरो अधिकार मंच इनीशिएटिव) से जुड़े रहे हैं, उस पर विपक्ष और मीडिया ने आरोप लगाया कि इसे विदेशी दूतावास खासकर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से फंडिंग मिली है। यूएसआईडी, एनईडी और कुछ यूरोपीय एनजीओ ने हामी को परोक्ष सहायता दी है। आलोचकों का दावा है कि इस तरह की संस्थाएं लोकतांत्रिक सुधार और सिविल सोसायटी को मजबूत करने के नाम पर पश्चिमी प्रभाव फैलाने का काम करती हैं। हालांकि सार्वजनिक ऑडिट में अमेरिकी सरकारी एजेंसियों से सीधी फंडिंग के ठोस प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं। काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास ने सफाई देते हुए कहा है कि नेपाल में दी जाने वाली कोई भी सहायता पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी हैं। यह केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों तक सीमित है। रूसी मीडिया संस्थान आरटी और स्पूतनिक ने नेपाल के काम युवा आंदोलन की तुलना यूक्रेन (2004, 2014) और जार्जियार (2003) जैसे रंग क्रांति अभियानों से की है। इन आंदोलनों की असंतोष पूर्ण भावनाओं का इस्तेमाल कर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका ने राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की थी। रूस का आरोप है कि नेपाल की मौजूदा अस्थिरता का पैटर्न भी वैसा ही है, जहां भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों के बीच विदेशी ताकतें अपने हित साधना चाहती हैं। रूस यह भी कह रहा है कि अमेरिका नेपाल में युवा शक्ति को एक सॉफ्ट टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ताकि भारत व चीन दोनों पर दबाव बनाया जा सके। यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह नेपाल की सत्ताधारी सरकार चीन के करीब आती जा रही थी उससे भी अमेरिका परेशान था।

प्रधानमंत्री 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री 71,850 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

प्रधानमंत्री बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे

क्षेत्रीय संपर्क को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री मणिपुर में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री असम में 18,350 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे

प्रधानमंत्री कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 से 15 सितम्बर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे।

13 सितंबर को प्रधानमंत्री मिजोरम का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइजोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 12:30 बजे चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा, वे दोपहर लगभग 2:30 बजे इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री असम का दौरा करेंगे और शाम लगभग 5 बजे गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

14 सितंबर को प्रधानमंत्री असम में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख अवसंरचना और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह सुबह लगभग 11 बजे दरंग में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह दोपहर लगभग 1:45 बजे गोलाघाट में असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वह गोलाघाट में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे।

15 सितंबर को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 9:30 बजे कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 2:45 बजे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वे पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। वे बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।

मिजोरम में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री आइजोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी।

विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 8,070 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। एक चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित इस रेल लाइन परियोजना में जटिल भौगोलिक स्थितियों के तहत 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं। मिजोरम और देश के बाकी हिस्सों के बीच सीधा रेल संपर्क क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, कुशल और किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करेगा। यह खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा, जिससे समग्र रसद दक्षता और क्षेत्रीय पहुंच बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री इस अवसर पर तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों, सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। आइजोल, अब एक राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा। सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस मिजोरम और असम के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस मिजोरम को सीधे कोलकाता से जोड़ेगी। इस बेहतर कनेक्टिविटी से अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें आइजोल बाईपास रोड, थेनजोल-सियालसुक रोड और खानकाउन-रोंगुरा रोड शामिल हैं।

प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डीईवीआईएनई) योजना के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 45 किलोमीटर लंबी आइजोल बाईपास सड़क का उद्देश्य आइजोल शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करना, लुंगलेई, सियाहा, लॉन्ग्टलाई, लेंगपुई हवाई अड्डे और सैरांग रेलवे स्टेशन आदि तक संपर्क में सुधार करना होगा। इससे दक्षिणी जिलों से आइजोल तक यात्रा का समय लगभग 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना एनईएसआईडीएस (सड़क) के तहत थेनजोल-सियालसुक रोड से कई बागवानी किसानों, ड्रैगन फल उत्पादकों, धान की खेती करने वालों और अदरक प्रसंस्करणकताओं को लाभ होगा, साथ ही आइजोल-थेनजोल-लुंगलेई राजमार्ग के साथ संपर्क मजबूत होगा। सेरछिप जिले में एनईएसआईडीएस (सड़क) के अंतर्गत खानकॉन-रोंगूरा सड़क बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी और इस क्षेत्र के विभिन्न बागवानी किसानों और अन्य लोगों को लाभ होगा, साथ ही नियोजित अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को भी समर्थन मिलेगा।

प्रधानमंत्री लॉन्ग्टलाई-सियाहा रोड पर छिमटुईपुई नदी पुल का भी शिलान्यास करेंगे। यह सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करेगा और यात्रा के समय को दो घंटे कम करेगा। यह पुल कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ढांचे के तहत सीमा पार व्यापार को भी बढ़ावा देगा।

प्रधानमंत्री खेल विकास के लिए खेलो इंडिया बहुउद्देशीय इंडोर हॉल की आधारशिला रखेंगे। तुइकुआल में स्थित यह हॉल एक बहुउद्देशीय इनडोर क्षेत्र सहित आधुनिक खेल सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे मिजोरम के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए लाभ और प्रोत्साहन मिलेगा।

इस क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री आइजोल के मुआलखांग में 30 टीएमटीपीए (हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष) क्षमता वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसका उद्देश्य मिजोरम और पड़ोसी राज्यों में एलपीजी की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे स्वच्छ रसोई ईंधन तक आसान पहुंच हो जाएगी। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना के तहत कवरथा में आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। मामित आकांक्षी ज़िले में स्थित इस विद्यालय में आधुनिक कक्षाएं, छात्रावास और कृत्रिम फुटबॉल मैदान सहित खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे 10,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं को लाभ होगा तथा दीर्घकालिक सामाजिक एवं शैक्षिक प्रगति की नींव रखेगी।

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री त्लांगनुआम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। यह विद्यालय नामांकन में सुधार करेगा, स्कूल छोड़ने की दर को कम करेगा और जनजातीय युवाओं के लिए समग्र शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा।

मणिपुर में प्रधानमंत्री

मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना; 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं; मणिपुर इन्फोटेक विकास (एमआईएनडी) परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें मंत्रीपुखरी में सिविल सचिवालय; मंत्रीपुखरी में आईटी एसईजेड भवन और नया पुलिस मुख्यालय; दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन; और चार जिलों में महिलाओं के लिए अनूठा इमा मार्केट शामिल हैं।

असम में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री 13 सितंबर को गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। यह समारोह डॉ. हजारिका के जीवन और विरासत का सम्मान करेगा, जिनका असमिया संगीत, साहित्य और संस्कृति में योगदान अद्वितीय है।

प्रधानमंत्री 14 सितंबर को असम में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री दरांग में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करेंगे; गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना, जो शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी, यातायात की भीड़भाड़ कम करेगी और राजधानी शहर और उसके आसपास संपर्क में सुधार लाएगी; और ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा-नरेंगी पुल, जो संपर्क में सुधार लाएगा और इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

गोलाघाट के नुमालीगढ़ में प्रधानमंत्री नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

वे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे, जो असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री

एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे और इसको संबोधित भी करेंगे। यह सशस्त्र बलों का शीर्ष-स्तरीय विचार-विमर्श मंच है, जो देश के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा भारत की सैन्य तैयारियों के भविष्य के विकास की नींव रखने के लिए एक साथ लाता है।

दो साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है - 'सुधारों का वर्ष-भविष्य के लिए परिवर्तन'।

बिहार में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। यह बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा, फसलोत्तर प्रबंधन को मजबूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा तथा मखाना के बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा।

देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 90% है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया जैसे प्रमुख ज़िले मखाना उत्पादन के प्राथमिक केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी मखाना की उच्च गुणवत्ता में योगदान करती है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से राज्य और देश में मखाना उत्पादन को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर बिहार की उपस्थिति और मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री पूर्णिया हवाई अड्डे के न्यू सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इस क्षेत्र में यात्री प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री भागलपुर के पीरपैंती में 3७800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसे अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल, कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है। यह परियोजना समर्पित बिजली प्रदान करेगी और बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।

प्रधानमंत्री 2680 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कोसी-मेची अंतर-राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में नहर के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें गाद निकालना, क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण और सेटलिंग बेसिन का जीर्णोद्धार शामिल है। साथ ही, इसकी जल-निकासी क्षमता को 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक किया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर बिहार के कई जिलों को सिंचाई विस्तार, बाढ़ नियंत्रण और कृषि मजबूती का लाभ मिलेगा।

रेल सम्पर्क में सुधार लाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री बिहार में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा कई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री बिक्रमशिला-कटारिया के बीच 2,170 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेल लाइन की आधारशिला रखेंगे, जो गंगा नदी के पार सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगी। इससे गंगा के पार सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा और इस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा।

प्रधानमंत्री अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) के बीच 4,410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) खंड पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे अररिया और किशनगंज जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा और पूर्वोत्तर बिहार में पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। वे जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जैसे जिलों को सीधा लाभ होगा। वे सहरसा और छेहरटा (अमृतसर) तथा जोगबनी और इरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें आधुनिक इंटीरियर, बेहतर सुविधाएं और तेज यात्रा क्षमताएं प्रदान करेंगी, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देंगी।

प्रधानमंत्री पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक अत्याधुनिक वीर्य केंद्र है, जो सालाना 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है। यह सुविधा, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली है, जो अक्टूबर 2024 में शुरू की गई स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है और जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ संरेखित है। मादा बछड़ों के जन्म की संभावना बढ़ाकर यह प्रौद्योगिकी छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को अधिक प्रतिस्थापन बछिया प्राप्त करने, आर्थिक तनाव को कम करने और बेहतर डेयरी उत्पादकता के माध्यम से आय बढ़ाने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री पीएमएवाई (आर) के तहत 35,000 ग्रामीण लाभार्थियों और पीएमएवाई (यू) के तहत 5,920 शहरी लाभार्थियों के लिए आयोजित गृह प्रवेश समारोह में भी भाग लेंगे और कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे।

प्रधानमंत्री बिहार में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशनों को लगभग 500 करोड़ रुपये का सामुदायिक निवेश कोष भी वितरित करेंगे तथा कुछ सीएलएफ अध्यक्षों को चेक सौंपेंगे।

अफीम पोस्त की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा

सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 के मद्देनजर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्त की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की

लगभग 1.21 लाख किसान लाइसेंस हासिल करने के पात्र हैं- किसान लाइसेंस में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, इन तीन राज्यों में पिछले फसल वर्ष की तुलना में अतिरिक्त 15,000 अतिरिक्त किसानों को शामिल किया गया है

(जीएनएस)। केंद्र सरकार ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस संबंधी वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की। यह नीति 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 फसल वर्ष के दौरान जारी रहेगी।

नीति की सामान्य शर्तों के अनुसार, इन राज्यों में लगभग 1.21 लाख किसान अफीम की खेती के लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र है। यह पिछले फसल वर्ष में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या से 23.5 प्रतिशत अधिक है । इस प्रकार लगभग 15,000 अतिरिक्त किसान इस नीति से जुड़े है, जिन्हें इस वर्ष अफीम की खेती से लाभ मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार चिकित्सा और उपशामक देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल्कलॉइड की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, आवश्यक मादक औषधियों के उत्पादन हेतु एल्कलॉइड की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, स्वदेशी और आत्मनिर्भर उपायों के माध्यम से प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

वार्षिक लाइसेंस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

मौजूदा अफीम गोंद उत्पादकों को बनाए रखना जिन्होंने प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम या उससे अधिक औसत मॉर्फिन उपज (एमक्यूवाई-एम) हासिल की है

3.0 किलोग्राम से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच मॉर्फिन उपज वाले मौजूदा अफीम गोंद उत्पादक अब पांच साल की लाइसेंस वैधता के साथ, पोस्ता भूसा सांद्रण (सीपीएस) विधि के तहत चीरा लगाए बिना पोस्ता भूसे की खेती करने के पात्र हैं।

इसके अलावा, 1995-96 से किसानों की संख्या के कंप्यूटराइजड रिकॉर्ड (डिजिटलीकरण) से समावेशिता बढ़ी है, जिससे पिछले वर्षों के सीमांत किसानों को निर्धारित पात्रता और शिथिल मानदंडों को पूरा करके लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिली है।

सरकार का बेहतर प्रदर्शन करने वाले उन किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने 900 किलोग्राम/हेक्टेयर या उससे अधिक अफीम की उपज प्राप्त की है, और उन्हें अफीम गोंद की खेती की पारंपरिक विधि अपनाने का विकल्प प्रदान करती है। इस बदलाव का उद्देश्य उनकी जोतों से अफीम की अधिक पैदावार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यह खेत से अफीम के अन्य स्रोतों के उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण तंत्र के रूप में भी कार्य करेगा।

सरकार सीपीएस खेती के तहत फसल वर्ष 2025-26 के लिए उन किसानों के लाइसेंस निलंबित करेगी, जिन्होंने पिछले फसल वर्ष (2024-25) के दौरान 800 किलोग्राम/हेक्टेयर की निर्धारित न्यूनतम योग्यता उपज (एमक्यूवाई) को पूरा नहीं किया था।

सरकार अपने अफीम और अल्कलॉइड कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष, नीमच स्थित सरकारी अल्कलॉइड कारखाने को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से जीएमपी प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी नियंत्रित अल्कलॉइड इकाइयों के लिए आत्मनिर्भरता को संतुलित करने के साथ अल्कलॉइड एपीआई और फॉर्मूलेशन में भारतीय दवा कंपनियों को सहयोग प्रदान करना है।

अहमदाबाद में बैंकरों और पेंशनभोगियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 13 सितंबर 2025 को अहमदाबाद में बैंकरों और पेंशनभोगियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा

(जीएनएस)। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के निदेर्शों के अनुरूप पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) 13 सितंबर, 2025 को अहमदाबाद में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के लिए एक बैंकर जागरूकता कार्यशाला और अहमदाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों के पेंशनभोगियों के लिए एक पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। ये दोनों कार्यक्रम सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू) श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सरकार की "जीवन को आसान बनाने" पहल के तहत पेंशनभोगियों के लिए आयोजित किए जाएंगे।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) पेंशन नीति में सुधार लाने और पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में सबसे आगे रहा है। एक बड़ा कदम पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य नौ प्रमुख बैंकों के पेंशन पोर्टलों का एकीकरण रहा है, जिससे एक ही पोर्टल के माध्यम से पेंशन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच संभव हुई है। पेंशन वितरण प्राधिकरणों के रूप में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए डीओपीपीडब्ल्यू ने केंद्रीय पेंशन संसाधित केंद्रों (सीपीपीसी) और क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए संरचित जागरूकता कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों, प्रक्रियाओं और हालिया सुधारों से अच्छी तरह अवगत हों, जिससे पेंशन वितरण की समयबद्धता और सटीकता में सुधार हो सके।

अहमदाबाद में होने वाले कार्यक्रमों में पेंशनभोगियों के पोर्टल, सीसीएस पेंशन नियम, पारिवारिक पेंशन, कम्यूटेशन, सीपीईएनजीआरएएमएस शिकायत निवारण, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने और एनआरआई पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता तथा सीजीएचएस लाभों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने के लिए विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है।

इस कार्यक्रम को श्री प्रदीप कुमार (पश्चिम रेलवे), श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, डॉ. राजेश प्रसाद (पीएनबी) और श्री उन्नीकृष्णन (सीजीपीए) जैसे वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति संबोधित करेंगे। इसमें 250 से अधिक पेंशनभोगियों और लगभग 80 बैंक अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों को कम करना और भविष्य की डिजिटल पहलों को विकसित करने के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। यह कार्यक्रम पेंशनभोगियों को सशक्त बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उत्तरदायी एवं पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

अहमदाबाद स्टेशन से शिफ्ट की गई कुछ ट्रेनों का ठहराव पुनः बहाल

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) द्वारा पुनर्विकास कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों के टर्मिनल इनमें से कुछ प्रमुख ट्रेनों को पुनः अहमदाबाद स्टेशन से संचालित किया जा रहा है, जबकि कुछ ट्रेनों का ठहराव आगामी कुछ दिनों तक

अहमदाबाद स्टेशन से आगमन/प्रस्थान करने वाली ट्रेनें:

ट्रेन संख्या	गाड़ी का नाम	आगमन/प्रस्थान स्टेशन	प्रस्थान/आगमन समय	प्रभावी तिथि
12655	अहमदाबाद - एमजीआर चेन्नई सेंट्रल नवजीवन एक्सप्रेस	अहमदाबाद	21.25 बजे	13.09.2025
12656	एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस	अहमदाबाद	18.00 बजे	12.09.2025
12932	अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल एसी डबल डेकर एक्सप्रेस	अहमदाबाद	05.50 बजे	13.09.2025
19034	अहमदाबाद - वलसाड गुजरात क्वीन एक्सप्रेस	अहमदाबाद	18.10 बजे	13.09.2025
22953	मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस	अहमदाबाद	14.30 बजे	13.09.2025

वटवा के स्थान पर मणिनगर स्टेशन पर आगमन करने वाली ट्रेन:

ट्रेन संख्या	गाड़ी का नाम	परिवर्तित आगमन स्टेशन	आगमन समय	प्रभावी तिथि
12931	मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद गुजरात एसी डबल डेकर एक्सप्रेस	मणिनगर	21.35 बजे	13.09.2025 से 19.09.2025 तक

को अहमदाबाद से अस्थायी तौर पर मणिनगर, वटवा और असारवा स्टेशनों पर स्थानांतरित किया गया था। अब साबरमती स्टेशन पर यथावत रहेगा। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

निम्नलिखित ट्रेनों का साबरमती स्टेशन पर ठहराव यथावत रहेगा।

ट्रेन नंबर	ट्रेन का नाम	प्रारम्भिक स्टेशन से (JCO)	
		दिनांक से	दिनांक तक
12479	जोधपुर - बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी एक्सप्रेस	12-09-2025	19-09-2025
20495	जोधपुर - हडपसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस	14-09-2025	19-09-2025
20496	हडपसर-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस	13-09-2025	19-09-2025
22452	चंडीगढ़- बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस	14-09-2025	21-09-2025
22738	हिसार - सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस	14-09-2025	19-09-2025
22664	जोधपुर - चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस	09-09-2025	16-09-2025
22916	हिसार - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस	16-09-2025	23-09-2025
12998	बाड़मेर - बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस	11-09-2025	18-09-2025
22724	श्रीगंगानगर- हजूर साहेब नांदेड एक्सप्रेस	06-09-2025	20-09-2025
14701	श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस	12-09-2025	19-09-2025
14707	लालगढ़ - दादर रणकपुर एक्सप्रेस	12-09-2025	19-09-2025
12966	भुज - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस	12-09-2025	19-09-2025
12960	भुज - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस	08-09-2025	15-09-2025
22966	भगत की कोठी - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस	06-09-2025	20-09-2025
20824	अजमेर - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस	12-09-2025	19-09-2025
22992	भगत की कोठी - वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस	10-09-2025	27-09-2025
14702	बांद्रा टर्मिनस- श्रीगंगानगर अरावली एक्सप्रेस	12-09-2025	19-09-2025
20943	बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी हमसफर एक्सप्रेस	11-09-2025	18-09-2025
19016	पोरबंदर- दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस	12-09-2025	19-09-2025

यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करे। ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे पर रविवार, 14 सितंबर, 2025 को दिवसकालीन ब्लॉक नहीं पश्चिम रेलवे के बोरीवली एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन ब्लॉक

मुंबई, रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा (शनिवार/रविवार) अर्थात 13 / 14 सितंबर, 2025 की मध्यरात्रि को बोरीवली एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच अप तथा डाउन स्लो लाइनों पर 00.30 बजे से 04.30 बजे तक चार घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जायेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान अप स्लो लाइन की ट्रेनों को बोरीवली एवं अंधेरी स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर चलाने के लिए डायवर्ट किया जाएगा। परिणामस्वरूप, ये ट्रेनें प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण राम मंदिर स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। ब्लॉक के कारण, कुछ अप एवं डाउन ट्रेनें निरस्त रहेंगी तथा कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त व्यवस्थाओं पर ध्यान दें।

अतः पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर रविवार, 14 सितंबर, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

पोरबंदर-दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस 19 सितम्बर तक अहमदाबाद की बजाय साबरमती जं. स्टेशन पर करेगी ठहराव

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन पर आरएलडीए (RLDA) द्वारा किए जा रहे कार्यों के चलते प्लेटफार्म संख्या 8 पर ब्लॉक लिया गया है। इस कारण अहमदाबाद स्टेशन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्य के चलते पोरबंदर-दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 19016) का अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन पर ठहराव अस्थाई रूप से हटाया गया है। अब यह ट्रेन अहमदाबाद की बजाय साबरमती जंक्शन स्टेशन पर रुकेगी। पूर्व में इस ट्रेन का अहमदाबाद स्टेशन के ठहराव को 05 जुलाई, 2025 से 12 सितम्बर, 2025 तक हटाया गया था। इसे आगे बढ़ाकर अब 19 सितम्बर, 2025 तक लागू कर दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें। ट्रेन के समय, ठहराव और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

डबलिंग कार्य के चलते कानालुस-पोरबंदर और पोरबंदर-कानालुस लोकल ट्रेनें 15 अक्टूबर तक आंशिक रूप से रद्द रहेंगी

राजकोट मंडल के लाखाबावल-पीपली-कानालुस सेक्शन में चल रहे डबलिंग कार्य के कारण 15 अक्टूबर, 2025 तक कानालुस-पोरबंदर और पोरबंदर-कानालुस लोकल ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 59206 पोरबंदर-कानालुस लोकल

यह ट्रेन अब 15 अक्टूबर, 2025 तक पोरबंदर से प्रस्थान कर गोपजाम तक ही चलेगी तथा गोपजाम-कानालुस खंड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

- ट्रेन संख्या 59205 कानालुस-पोरबंदर लोकल

यह ट्रेन अब 15 अक्टूबर, 2025 तक कानालुस की बजाय गोपजाम स्टेशन से चलेगी और कानालुस-गोपजाम खंड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

यात्रियों से निवेदन

रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

टिकट चेकिंग स्टॉफ के लिए डिजिटल हाजिरी की सुविधा : भावनगर मंडल ने लागू की आधुनिक बायोमेट्रिक प्रणाली

भारतीय रेल ने टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक साइन-ऑन सिस्टम शुरू किया है। इसी पहल के तहत भावनगर रेल मंडल ने भी अपने टिकट चेकिंग स्टाफ (ळळए) की ड्यूटी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंडल के अंतर्गत सभी सात (7) टीटीई लॉबी में आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

पहले टिकट चेकिंग स्टाफ का साइन-ऑन और साइन-ऑफ कार्य यूजरनेम और पासवर्ड के माध्यम से किया जाता था। अब इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट डिवाइस को टीटीई लॉबी एप्लीकेशन से जोड़ा गया है और इसे सी-डैक पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

अब टीटीई अपनी ड्यूटी की शुरूआत में बायोमेट्रिक साइन-इन और ड्यूटी की समाप्ति पर साइन-आउट करेंगे। इस व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों की रीयल-टाइम उपस्थिति दर्ज होगी, बल्कि ड्यूटी रिकॉर्ड में पूर्ण पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी। इससे साइन-इन और साइन-आउट की प्रक्रिया तेज, सरल और सुरक्षित हो गई है।

टीटीई लॉबी एप्लिकेशन को सी-डैक (केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक संस्था) के पोर्टल से जोड़ा गया है। यह प्रणाली वर्तमान में भावनगर, बोटाद, महुवा, गांधीग्राम, पोरबंदर, जूनागढ़ और वेरावल स्थित टीटीई लॉबी में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।

बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होने से कर्मचारियों की उपस्थिति पर प्रभावी निगरानी संभव होगी और ड्यूटी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा गड़बड़ी पर रोक लग सकेगी। यह पहल न केवल रेलवे की डिजिटल इंडिया और स्मार्ट रेलवे मिशन को गति प्रदान करेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भी उल्लेखनीय सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी।

मंडल रेल प्रबंधक-भावनगर श्री दिनेश वर्मा ने इस तकनीकी पहल को लागू करने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी और भावनगर मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भावनगर मंडल हमेशा डिजिटल तकनीकों को अपनाने में अग्रणी रहा है और यह बायोमेट्रिक साइन-ऑन और साइन-ऑफ सिस्टम भी एक और डिजिटल पहल है, जो प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

टिकट चेकिंग स्टॉफ के लिए डिजिटल हाजिरी की सुविधा : भावनगर मंडल ने लागू की आधुनिक बायोमेट्रिक प्रणाली

(जीएनएस)।

वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कैसे सोने के नैनोकण - वे सूक्ष्म कण जो शक्तिशाली प्रकाशीय प्रौद्योगिकियों को जन्म देते हैं - अमीनो एसिड और लवण जैसे कुछ दैनिक अणुओं के संपर्क में आने पर अपना व्यवहार बदल देते हैं, जिससे अधिक स्मार्ट बायोसेंसर, बेहतर नैदानिक उपकरण और यहां तक कि अधिक विश्वसनीय दवा वितरण प्रणालियों का मार्ग प्रशस्त होता है।

सोने के नैनोकण विशेष हैं क्योंकि वे प्रकाश के साथ अनोखे तरीके से क्रिया करते हैं। उनका रंग और प्रकाशिक प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि वे अकेले हैं या एक साथ समूहित हैं। जब वे एकत्रित होते हैं, तो उनके प्रकाशिक गुण बदल जाते हैं, यही कारण है कि बायोसेंसर और इमेजिंग में उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन यह गुण एक दोधारी तलवार है—अनियंत्रित एकत्रीकरण इन प्रणालियों को अविश्वसनीय बना सकता है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करना वैज्ञानिकों का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान एसएन बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इस एकत्रीकरण या क्लस्टरिंग को नियंत्रित करने का एक तरीका खोज लिया है।

प्रोफेसर माणिक प्रधान के नेतृत्व में एक टीम ने दो अणुओं को प्रस्तुत किया - ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड (जीडी एनएच सीएल) - एक शक्तिशाली लवण जो प्रयोगशालाओं में प्रोटीन को तोड़ने के लिए जाना जाता है और एल-ट्रिप्टोफैन (एल-टीआरपी) - एक अमीनो एसिड जिसे हम प्रतिदिन लेते हैं, प्रोटीन में पाया जाता है और अक्सर नींद और विश्राम से जुड़ा होता है।

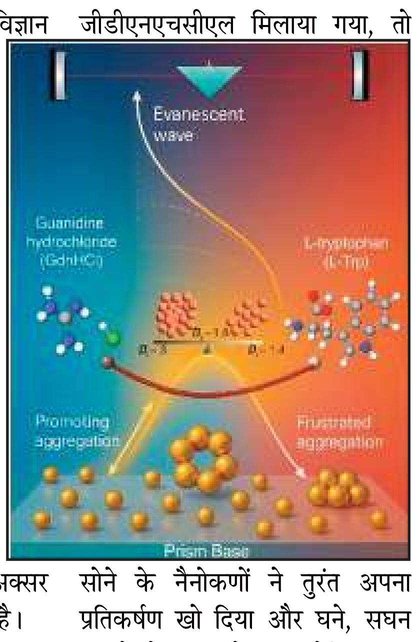

चित्र 1: यह ग्राफिक ईडब्ल्यू-सीआरडीएस का उपयोग करते हुए सोने के नैनोकणों के एकत्रीकरण की वास्तविक समय निगरानी को दशार्ता है, जहां क्षणभंगुर तरंग जीडीएनएचसीएल -प्रेरित एकत्रीकरण और एल-ट्रिप द्वारा इसके परिवर्तन की जांच करती है, जिसके परिणामस्वरूप असंतुष्ट एकत्रीकरण होता है।

उन्होंने पाया कि जब जीडीएनएचसीएल मिलाया गया, तो सोने के नैनोकणों ने तुरंत अपना प्रतिकर्षण खो दिया और घने, सघन समूहों में जमा हो गए। लेकिन जब जीडीएनएचसीएल के साथ एल-टीआरपी भी आया, तो कहानी बदल गई। सघन समूहों के बजाय, नैनोकणों ने ढीले, शाखित नेटवर्क बनाए।

शोधकर्ताओं ने इसे "असंतुष्ट एकत्रीकरण" कहा - मानो नैनोकण जुटना चाहते हों, लेकिन अमीनो एसिड उन्हें ऐसा करने से रोकता रहे।

सौम्यदीप्ता चक्रवर्ती, डॉ. जयेता बनर्जी, इंद्रायणी पात्रा, डॉ. पुष्पेंदु बारिक और प्रोफेसर माणिक प्रधान की टीम ने इस अध्ययन के लिए एक अत्यंत संवेदनशील प्रकाशिक तकनीक, एवेनसेंट वेव कैविटी रिंगडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (ईडब्ल्यू-सीआरडीएस) नामक एक अत्याधुनिक विधि का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि एल-टीआरपी ग्वानिडिनियम आयनों को स्थिर करता है, जिससे उनका प्रभाव कम हो जाता है। इससे एकत्रीकरण धीमा हो जाता है और एक नई, खुली संरचना बनती है।

ईडब्ल्यू-सीआरडीएस ने बेजोड़ संवेदनशीलता के साथ सतहों पर नाजुक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक पूरी तरह से नया मार्ग खोला है।

जर्नल एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित यह अग्रणी अध्ययन न केवल नैनोविज्ञान में मौलिक प्रश्नों का उत्तर देता है, बल्कि प्रकाश और पदार्थ के अध्ययन के प्रारुप के क्षेत्र को भी बढ़ाता है।

लोक सभा अध्यक्ष तिरुपति में संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की महिला सशक्तीकरण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल; आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री; केंद्रीय मंत्री; राज्य सभा के उपसभापति; आंध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष; संसद और राज्य विधानमंडलों में महिला सशक्तीकरण संबंधी समितियों के सभापति इस सम्मेलन में भाग लेंगे

संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के 100 से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे

सम्मेलन का विषय है "उभरती प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना"

(जीएनएस)।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 14 सितंबर 2025 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की महिला सशक्तीकरण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री बिरला इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे।

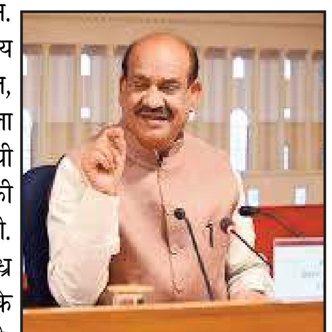

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, श्री एस. अब्दुल नजीर; आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री एन. चंद्रबाबू नायडू; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति की सभापति, श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी; आंध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री सी. अय्यन्नापत्रुडु; और आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सभापति, श्री कोये मोशेनु राजू उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य तथा संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की महिला सशक्तीकरण संबंधी समितियों के सभापति और सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन (14-15 सितंबर 2025) में पूरे देश से 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय "उभरती प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना" है। "विकसित भारत के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास" और दो उप-विषयों (i) 'जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग' और (ii) 'उभरती प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना' को भी एजेंडा में शामिल किया गया है।

इस सम्मेलन में भारत में डिजिटल क्षेत्र में हो रही प्रगति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा के अवसरों और जोखिमों तथा महिलाओं पर उनके प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा । डिजिटल क्षेत्र में महिला-पुरुष अंतराल को दूर करने, रळएट क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने, डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्यमिता एवं नवाचार में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। ह्यवर्ष 2047 तक विकसित भारतह्न के विजन को साकार करने के लिए इस सम्मेलन में उभरती प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के समावेशन की रणनीतियों पर विचार किया जाएगा ।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, श्री एस. अब्दुल नजीर; लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति की सभापति, श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी और आंध्र प्रदेश विधान सभा के सभापति, श्री सी. अय्यन्नापत्रुडु 15 सितंबर 2025 को आयोजित किए रहे समापन सत्र को संबोधित करेंगे । आंध्र प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष धन्यवाद ज्ञापित करेंगे ।

तिरुपति में आयोजित किया जा रहा महिला सशक्तीकरण संबंधी समितियों का यह पहला सम्मेलन, महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय संवाद का प्रतीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी परिवर्तन के युग में महिलाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करना है।

आयुष मंत्रालय के पीसीआईएमएंडएच ने नियामक और गुणवत्ता पेशेवरों के लिए एएसयूएंडएच दवाओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फामाकीपिया आयोग ने 8 से 12 सितंबर, 2025 तक गाजियाबाद स्थित अपने मुख्यालय में पाँच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के लिए नियामक ढाँचे, गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना था।

इस प्रशिक्षण में भारत भर से नियामक निकायों, अनुसंधान परिषदों, दवा उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये व्यापक सत्र औषधि प्रवर्तन अधिकारियों, गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों और दवा निमार्ताओं को फामाकीपियल मानकों और उत्तम विनिर्माण प्रथाओं में उन्नत ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव से लैस करने के लिए डिजाइन किए गए थे।

कार्यक्रम का उद्घाटन एनसीआईएसएम के आचार एवं पंजीकरण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रो. (वैद्य) राकेश शर्मा ने किया। एनसीएच के होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन सत्र का संचालन पीसीआईएमएंडएच के निदेशक डॉ. रमन मोहन सिंह ने किया।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

पहला और दूसरा दिन

तकनीकी सत्रों में फामाकीग्नोस्टिक पहचान, फाइटोकेमिकल विश्लेषण और जीएमपी अनुपालन के साथ-साथ फामाकीग्नोसी और रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल था।

तीसरा दिनः

व्याख्यान शेल्फ-लाइफ अध्ययन और विनियामक ढांचे पर केंद्रित थे, जिसके बाद डॉ. विलमार श्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नोएडा) और हमदर्द ल ै ब ो र े ट र ी ज (गाजियाबाद) के औद्योगिक दौरे हुए, जिससे वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त हुआ।

चौथा दिनः

सत्रों में सूक्ष्म-जीव विज्ञानी एवं औषधीय मूल्यांकन, धातु एवं खनिज औषधियों का मानकीकरण, और नियामक पहलू शामिल थे। प्रतिभागियों ने प्रयोगशाला प्रशिक्षण में भी भाग लिया और परिसर में स्थित हर्बल गार्डन का भी दौरा किया।

दिन 5:

समापन सत्र में एनएबीएल मान्यता, जीएमपी और सिद्ध औषधियों के मानकीकरण पर चर्चा हुई।

समापन सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉ. ए.एस. ने की। के.रामचंद्र रेड्डी, कुलपति, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय (मुख्य अतिथि); डॉ. ए.एस. नीलिमा मिश्रा, निदेशक, राष्ट्रीय जैविक संस्थान (सम्मानित अतिथि); और डॉ. पंकज जौहरी, निदेशक, एनएबीपी-क्यूसीआई (विशेष अतिथि) के रूप में शामिल हुए

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के विशेषज्ञ-निर्देशित व्याख्यानों, व्यावहारिक प्रयोगशाला सत्रों और क्षेत्रीय दौरों के अनूठे मिश्रण की खूब सराहना की। इस प्रशिक्षण ने फामाकीपियल मानकों, जीएमपी और नियामक अनुपालन के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे एएसयूएंडएच दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बल मिला।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की

इस कार्यशालाओं में तथ्यों की जानकारी देने और भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने पर जोर दिया गया

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यक्रम में 51 मीडिया नोडल अधिकारियों (एमएनओ) और सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों (एसएमएनओ) ने हिस्सा लिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे के मद्देनजर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत में संविधान के अनुसार चुनाव सख्ती से कराए जाते है और भ्रामक सूचनाओं का तथ्यों के साथ खंडन किया जाना चाहिए।

मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ समय पर तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए सीईओ कार्यालयों के संचार संत्र को मजबूत करने के लिए सत्र आयोजित किए गए।

कार्यशाला में मीडिया और सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर समर्पित सत्र आयोजित किए गए ।

गलत सूचनाओं का खंडन करने के लिए विभिन्न उपकरणों, तकनीकों और रणनीतियों पर एक विशेषज्ञ सत्र भी आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम इस तरह का तीसरा संवादात्मक आयोजन था। इससे पहले, आईआईआईडीईएम के सीईओ कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए 9 अप्रैल, 2025 और 5 जून, 2025 को नई दिल्ली में नीतिगत कार्यक्रम (ओरिएंटेशन प्रोग्राम) आयोजित किए गए थे।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने माउंट आबू स्थित ब्रह्माकुमारीज मुख्यालय का दौरा किया

श्री जाधव ने माउंट आबू में मन-शरीर चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

श्री जाधव ने ब्रह्माकुमारीज के औषधीय वृक्षारोपण प्रयासों को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के समर्थन का आश्वासन दिया

श्री जाधव ने ब्रह्माकुमारीज के आध्यात्मिक कार्यों की सराहना की, माउंट आबू में ध्यान सत्र में भाग लिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने माउंट आबू का एक दिवसीय दौरा कर समग्र स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।

श्री जाधव ने ब्रह्माकुमारीज द्वारा "मन-शरीर चिकित्साः स्व-देखभाल माध्यम से स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व" पर ज्ञान सरोवर में आयोजित 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया । श्री जाधव ने अपने संबोधन में, ध्यान, आंतरिक शक्ति और समग्र जीवन के संदेश के प्रसार में ब्रह्माकुमारीज के दशकों के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्व-देखभाल पर ब्रह्माकुमारीज का जोर प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के पूर्णतया अनुरूप है, जो आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ समेकित करने के पक्षधर हैं। श्री जाधव ने कहा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तेजी से प्रगति के साथ ही ये पहल रेखांकित करती हैं कि सच्चा स्वास्थ्य मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

श्री जाधव ने ज्ञान सरोवर में ब्रह्माकुमारी शिवानी दीदी के साथ सार्थक चर्चा भी की। उन्होंने विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह ही समर्पित "ध्यान दिवस" मनाने के उनके प्रस्ताव की सराहना की और इस पर अपना समर्थन व्यक्त किया।

श्री जाधव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में, कहा कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ब्रह्माकुमारीज के कृषि प्रभाग के नेतृत्व में वृक्षारोपण पहल का समर्थन करेगा, जिससे समग्र स्वास्थ्य प्रचलन में औषधीय और आध्यात्मिक पौधों के उपयोग को बढ़ावा मिले।

श्री जाधव ने ब्रह्माकुमारीज के कई प्रमुख संस्थानों का भ्रमण किया, जिनमें शांति स्तंभ, ग्लोबल हॉस्पिटल, पांडव भवन और कला दीर्घ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थान सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार करते हैं, जिससे वहां आने वालों को गहन आंतरिक शांति और भावनात्मक संतुलन का अनुभव होता है।

श्री जाधव ने एक ध्यान सत्र में भी भाग लिया, और इसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बताया। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे अनुभव आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, मानसिक एकाग्रता को प्रखर बनाते हैं और अधिक संतुलित एवं सकारात्मक जीवन जीने के मार्गदर्शक प्रकाशपुंज का काम करते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ एक संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से ऑटो घटक क्षेत्र के लिए विकास, सहयोग एवं नवाचार के नए अवसर खुलेंगे: श्री गोयल

भारत-यूरोपीय संघ वर्ष के अंत तक एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं: यूरोपीय संघ आयुक्त

हाल ही में हुआ जीएसटी सुधार ऑटो उद्योग के लिए ऐतिहासिक राहत है: श्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के 65वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापक एवं संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं जिससे दोनों पक्षों के व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रकार का समझौता एकतरफा नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक वार्ता को निष्पक्ष एवं संतुलन बनाने के लिए कुछ हद तक लेन-देन शामिल किया जाता है।

मंत्री ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक आदर्श समझौते को प्रगति का दुश्मन नहीं बनने दिया जाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वार्ता बहुत सकारात्म दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया के माध्यम से उजागर हो रही संभावनाओं के प्रति आशा व्यक्त किया जो विशाल है और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं गहन आर्थिक भागेदारी का अवसर खोलेगी।

श्री गोयल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ऑटोमोटिव घटक क्षेत्र जैसे साहसिक एवं दूरदर्शी उद्योग, जो पहले की एफटीए वाताओं से लगातार मजबूत हुआ है, को भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी के अंतर्गत तैयार किए जा रहे प्रावधान आकर्षक एवं संभावनाओं से भरपूर लगेंगे।

उन्होंने आशा व्यक्त किया कि ऑटोमोटिव घटक क्षेत्र, जिसने हमेशा एफटीए वाताओं को मजबूती प्रदान की है, को भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो रही व्यवस्थाएं आकर्षक एवं रोमांचक लगेंगी तथा उनमें व्यवसायों के विकास, सहयोग, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास में शामिल होने की भरपूर संभावनाएं होंगी। मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र ने भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता का समर्थन करके एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत होकर लगातार लचीलापन एवं दूरदृष्टि दिखाई है।

श्री गोयल ने कहा कि एफटीए भारतीय निमार्ताओं के लिए अपने यूरोपीय समकक्षों और विश्व के अन्य क्षेत्रों की कंपनियों के साथ साझेदारी करने का नया मार्ग खोलेगा, जिससे संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी साझेदारी और सहयोगात्मक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जहां तक लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का सावाल है

तो भारत महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है चाहे वह डिजाइन, विकास या अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र हों और देश में कुशल प्रतिभा भंडार के साथ यह भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना देगा। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की साझेदारियां लागत में कमी लाने, उत्पादकता बढ़ाने, भारतीय युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने और देश को उच्च-गुणवत्ता वाले ऑटोमोटिव घटक निर्माण का एक अग्रणी केंद्र बनाने में मदद करेंगी।

इस सत्र को यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा, अंतर-संस्थागत संबंध एवं पारदर्शिता आयुक्त, महामहिम मारोस शेफोविच ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ अभूतपूर्व गति से एक अभूतपूर्व मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्तमान चर्चा को दोनों भागीदारों के बीच अब तक की सबसे गहन एवं रचनात्मक चचाओं में से एक कहा। उन्होंने कहा कि यद्यपि मुक्त व्यापार समझौते पर पहले भी बातचीत के प्रयास किए गए लेकिन इससे पहले यह प्रक्रिया इतनी गंभीर, आपसी विश्वास और साझा महत्वाकांक्षा के स्तर तक कभी नहीं पहुंची थी। आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन द्वारा पूर्व में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप इस वर्ष के अंत तक बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों पक्ष एक ऐसा आर्थिक रूप से सार्थक पैकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उत्पादकों, निर्यातकों एवं उपभोक्ताओं के हितों को समान रूप से संतुलित करे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य एक ऐसे वास्तविक लाभप्रद समझौते पर पहुंचना है जो न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाए बल्कि दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, सतत प्रथाओं और गहन सहयोग को भी बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि भारत तेज गति से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन बन रहा है और भारत के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी यूरोपीय संघ के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक उसी तरह जैसे यूरोपीय प्रौद्योगिकी एवं पैमाने से भारत के विकास को लाभ प्राप्त होगा।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक तत्वों से युक्त एक व्यापक आर्थिक साझेदारी होगी। उन्होंने कहा कि भारत को यूरोप की तकनीक एवं नवाचार से लाभ होगा जबकि यूरोपीय संघ को भारत के विकास, पैमाने एवं लचीलेपन से लाभ होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ जी से आज लखनऊ में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोक सभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शिष्टाचार भेंट की।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने झारखंड में सीसीएल के मगध-संघमित्रा क्षेत्र का दौरा किया

श्री जी. किशन रेड्डी ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की

मंत्री ने जेएसएसपीएस में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया, रांची में आईबीएम क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और कोयला खनन कार्यों की समीक्षा की

(जीएनएस)।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने झारखंड यात्रा के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, सामुदायिक कल्याण और खेलों को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

इससे पहले, श्री रेड्डी ने होटवार के खेलगाँव स्थित झारखंड राज्य खेल

संवर्धन समिति (जेएसएसपीएस) का दौरा किया। प्रशिक्षुओं ने एक पौधा भेंटकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री महोदय ने युवा खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों से बातचीत की, उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

श्री रेड्डी ने जेएसएसपीएस में नव स्थापित फिजियोथेरेपी केंद्र का भी निरीक्षण किया और उसकी सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मंत्री महोदय ने अनोखे अंदाज में सितंबर में जन्मे 16 बच्चों का जन्मदिन केक काटकर, उपहार भेंट करके और आशीर्वाद देकर मनाया। श्री रेड्डी ने युवा खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने खिलाड़ियों से कठोर प्रशिक्षण जारी रखने और राज्य एवं देश का नाम रोशन करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि सीसीएल और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल, जेएसएसपीएस, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और तीरंदाजी सहित 11 खेलों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करती है।

भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को कमीशन किया

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना के नवीनतम नौसैनिक बेस, आईएनएस अरावली को 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में कमीशन किया गया।

एक शानदार कमीशनिंग समारोह में, नौसेना प्रमुख को 50 जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूनिट के पहले कमांडिंग ऑफिसर, कैप्टन सचिन कुमार सिंह ने संस्कृत में मंगलाचरण का पाठ किया और उसके बाद कमीशनिंग वारंट पढ़ा। एनडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष श्रीमती शशि त्रिपाठी ने कमीशनिंग पट्टिका के अनावरण के बाद, राष्ट्रीय गान की धुन पर नौसेना ध्वज फहराया। राष्ट्रीय गान के अंतिम स्वर के साथ ही मस्तूल पर कमीशनिंग पताका फहरा दी गई।

कमीशनिंग समारोह में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, वीसीएनएस, वाइस एडमिरल तरुण सोबती, डीसीएनएस, वरिष्ठ नौसेना अधिकारी और विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

नौसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि आईएनएस अरावली एक मजबूत प्रशासनिक और लॉजिस्टिक

सहायता के लिए आधार प्रदान करता है, जो सुविधाओं के बढ़ने और जटिलता के अनुरूप है, जिससे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है। "यह नया बेस न केवल प्रौद्योगिकी का हब होगा, बल्कि हमारे प्लेटफार्मों और साझेदारों को महासागरों के पार जोड़ने वाला सहयोग का केंद्र भी होगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सहयोगात्मक दृष्टिकोण, अर्थात महासागर, यानी (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रीजन) का सच्चा प्रतीक है, और हिंद महासागर क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा।"

कमांडिंग ऑफिसर और कमीशनिंग क्रू को बधाई देते हुए नौसेना प्रमुख ने उन्हें नौसेना के कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया, "जैसा कि आप सूचना प्रभुत्व के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं।"

आईएनएस अरावली, जिसका नाम अविचल अरावली पर्वतमाला से लिया गया है, भारतीय नौसेना के विभिन्न सूचना और संचार केंद्रों को सहायता प्रदान करेगा, जो भारत और भारतीय नौसेना के कमांड, नियंत्रण और समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं।

'समुद्रिकसुरक्षायाः सहयोगंह्ल या ह्यसहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षाह्ल के आदर्श वाक्य से प्रेरित है और नौसेना बेस सहायक और सहयोगी लोकाचार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो नौसेना इकाइयों, एमडीए केंद्रों और संबद्ध हितधारकों के साथ सहजता से काम करता है।

बेस के शिखर पर केन्द्रीय पर्वतीय छवि है जो अटूट और मजबूत अरावली पर्वतमाला का प्रतीक है, तथा उगता हुआ सूर्य शाश्वत सतर्कता, सुदृढ़ता और ऊर्जा का प्रतीक है, साथ ही संचार और एमडीए के क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी क्षमताओं के उदय का भी प्रतीक है।

इस प्रकार, यह शिखर भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए शाश्वत सतर्कता को सुगम बनाने हेतु बेस की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत का आयोजन

शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने और पारिवारिक पेंशनभोगियों के सम्मान एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

(जीएनएस)। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर ह्यसंपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के लिए पेंशन अदालतों के आयोजन की पहल की सराहना की। उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला कि इस पहल ने न केवल शिकायतों के निवारण में तेजी लाई है, बल्कि समाज में सक्रिय योगदानकर्ता के तौर पर पेंशनभोगियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया है।

रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे, आवास एवं शहरी मामलों, नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय आदि के अंतर्गत आने वाले 21 विभागों/ मंत्रालयों से जुड़े अति वरिष्ठ एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की 894 शिकायतों को निवारण के लिए अदालत में लाया गया, जिनमें से 652 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे पेंशनभोगियों को मौके पर न्याय दिलाने में इस पहल की दक्षता का पता चलता है।

10.09.2025 को आयोजित अदालत में दिल को छू लेने वाली सफलता की कई कहानियां सामने आईं। पेंशनभोगियों के अनुभव किए गए संघर्षों और पेंशन अदालत की व्यवस्था ने उन्हें लंबे समय से लंबित अपने वाजिब हक दिलाने में कैसे योग्य बनाया, यह समझने के लिए कुछ मामलों के अंश नीचे दिए गए हैं।

श्रीमती शिशल

राजस्थान निवासी श्रीमती शिशल देवी स्वर्गीय चल्लू राम की पत्नी हैं। उनके पति का 15-11-2006 को निधन हो गया था और उन्हें 31-10-2012 तक पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर का भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने पेंशन की तिथि से 7 वर्ष के लिए बढ़ी हुई दर में संशोधन और बकाया राशि के तत्काल भुगतान का अनुरोध किया था। अदालत में रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए कार्यालय ने जानकारी दी कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और 1,91,715/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है और भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

श्रीमती बाल कंवर

श्रीमती बाल कंवर, जो राजस्थान की रहने वाली हैं और स्वर्गीय सांग सिंह की विधवा हैं, अपनी पारिवारिक पेंशन में संशोधन और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की मांग कर रही थीं। अदालत में रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए कार्यालय ने जानकारी दी कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और 01.07.2019 से 31.07.2025 तक का 1,50,155/- रुपये का बकाया उनके खाते में जमा कर दिया गया है।

श्रीमती शशि देवी

उत्तर प्रदेश की श्रीमती शशि देवी अपने पति स्वर्गीय श्री राम नरेश यादव के बकाया ओआरओपी बकाया के लिए अनुरोध कर रही थीं। उन्हें भुगतान न होने का प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

अदालत में रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए कार्यालय ने जानकारी दी कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और ओआरओपी-क्क के संबंध में सेवा पेंशन और विकलांगता पेंशन तथा 01.07.2019 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर के 2,92,120/- रुपये के बकाया का भुगतान कर दिया गया है और अगले महीने के भुगतान चक्र से इसे जमा कर दिया जाएगा।

श्रीमती मोनिका देब

स्वर्गीय सिपाही शांति कुमार देब की विधवा श्रीमती मोनिका देब असम की निवासी हैं। उन्होंने 20 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि के लिए अपने पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान का अनुरोध किया था। रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए कार्यालय ने अदालत में जानकारी दी कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और 01/19 से 02/22 तक के बकाया ₹4,97,845 का भुगतान कर दिया गया है और जल्द ही उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

श्रीमती कुसम रानी

श्रीमती कुसम रानी पंजाब की रहने वाली हैं। उनके दिवंगत पति, श्री देवी दयाल, पूर्व एमटी ड्राइवर, मिलिट्री फार्म, जालंधर कैंट, 31.05.2014 को सेवानिवृत्त हुए और 26.10.2023 को उनका निधन हो गया। उन्हें 20.09.2012 को आरोप पत्र दिया गया था, लेकिन उनके जीवनकाल में जांच पूरी नहीं हो पाई थी। हालांकि, उनके निधन के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही बंद कर दी गई थी, फिर भी बार-बार अनुरोध करने के बावजूद रोकी गई ग्रेच्युटी जारी नहीं की गई। रक्षा मंत्रालय के सीजीडीए और पीसीडीए कार्यालय ने अदालत में जानकारी दी कि उनका मामला सुलझा लिया गया है और 5,07,210/- रुपये की ग्रेच्युटी जारी कर दी गई है।

श्रीमती मान कौर

राजस्थान की श्रीमती मान कौर 01.10.2020 से 100% अतिरिक्त पेंशन की प्रतीक्षा कर रही थीं। पेंशन में संशोधन किया गया था, लेकिन 01.10.2020 से अब तक का बकाया भुगतान नहीं किया गया है।

मत्स्य पालन विभाग सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संधारणीय समुद्री विकास के लिए आइसलैंड के साथ साझेदारी की

मत्स्य पालन विभाग सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संधारणीय समुद्री विकास के लिए आइसलैंड के साथ साझेदारी की

शून्य-अपशिष्ट मत्स्य क्षेत्र और आइसलैंड के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहयोग से भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी

प्रविष्टि तिथिः 12 एएढ 2025 2:42ढट ु८ ढक्ह ऊै

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी के नेतृत्व में सचिव-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 से 12 सितंबर 2025 तक आइसलैंड के रेक्जाविक की तीन दिवसीय यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी, निवेश संवर्धन और नवोन्मेष आदान-प्रदान के जरिए मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना है।

डॉ. लिखी ने 11 सितंबर को रेक्जाविक में आइसलैंड महासागर क्लस्टर (आईओसी) के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की, जिसमें भारत में विशेष रूप से शून्य अपशिष्ट मत्स्य उद्योग और जलीय कृषि क्लस्टर विकसित करने में सहयोग पर चर्चा हुई, । विमर्श में भारत की व्यापक उत्पादन क्षमता के साथ ही आइसलैंड के संवहनीय समुद्री प्रथाओं की तकनीकी क्षमता का लाभ उठाने पर विचार किया गया। दोनों पक्षों ने भारत में आइसलैंड के समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निवेश अवसरों के साथ ही व्यापार-से-व्यापार (बी2बी) संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उपायों की चर्चा की। इस क्षेत्र में संधारणीयता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मछली प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, अन्वेषण क्षमता तथा प्रमाणन में नवाचार

सहयोग पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्लस्टर विकास के लिए भारत का रूख प्रस्तुत किया, जिसमें निवेश, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों का उल्लेख किया गया। बीआरआईएम और हैम्पायोजेन सहित आइसलैंड की कंपनियों ने आइसलैंड महासागर क्लस्टर के साथ मिलकर आइसलैंड के अग्रणी अपशिष्ट रहित मॉडल और अत्याधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की जानकारी साझा की। बैठक में आइसलैंड में भारत के राजदूत श्री आर. रवींद्र और रेक्जाविक स्थित भारतीय दूतावास के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आइसलैंड की ओर से प्रमुख प्रतिभागियों में आइसलैंड महासागर क्लस्टर के संस्थापक और अध्यक्ष श्री थोर सिगफसन और स्टार्टअप आइसलैंड के संस्थापक श्री बाला कमालाखारन शामिल हुये। डॉ. लिखी ने आइसलैंड की अग्रणी खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास कंपनी मैटिस का भी दौरा किया, जहां उन्हें कंपनी की खाद्य सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और संघारणीय समुद्री संसाधन उपयोग के क्षेत्र में कार्यों की जानकारी दी गई। इस यात्रा से भारत के मत्स्य क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहयोग के नए मार्ग प्रशस्त हुए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 सितंबर को रेक्जाविक के लॉगार्डलशोल में आइसलैंड के फिशिंग एक्सपो 2025 का दौरा किया, जहां डॉ. लिखी ने आइसलैंड की उद्योग मंत्री सुश्री हन्ना कैट्रिन फ्रिड्रिक्सन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्रों में विकास और संस्थागत एवं वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संधारणीय मत्स्य क्षेत्र में नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रचलन के बारे में जानकारी के लिए आइसलैंड के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र संघों, एजेंसियों और उद्यमियों के साथ भी बातचीत की। दोनों पक्षों ने एक अलग विषयगत चर्चा में भविष्य में सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें अपशिष्ट रहित मत्स्य और जलीय कृषि समूहों की स्थापना, और प्रसंस्करण सुविधाओं, ट्रांस-शिपमेंट क्षमताओं, मूल्यवर्धन तंत्रों और मजबूत ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन प्रणाली से लैस समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों की तैनाती शामिल है। बातचीत में नियामक निगरानी और संसाधन प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए उन्नत पोत चौकसी और निगरानी (वीएमएस) प्रणाली अपनाने के साथ ही समुद्र में मछली पकड़ने की तकनीकों में प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने भारत के पहाड़ी राज्यों में ट्राउट पालन (समशीतोष्ण क्षेत्र मछली प्रजाति), स्वास्थ्य प्रबंधन और विपणन को बढ़ावा देने के साथ ही अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में टूना और टूना जैसी प्रजातियों के विशेष मत्स्य तकनीक विकसित करने में सहयोग की संभावना पर चर्चा की।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से भारत और आइसलैंड के बीच सहयोग में आशाजनक वृद्धि हुई और इससे मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, औद्योगिक साझेदारी और नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

आइसलैंड महासागर क्लस्टर

आइसलैंड महासागर क्लस्टर (आईओसी) आइसलैंड के रेक्जाविक में स्थित एक नवाचार और व्यावसायिक नेटवर्क है, जो समुद्री और महासागरीय क्षेत्र में संघारणीय विकास के लिए समर्पित है। वर्ष 2011 में पोर सिगफसन द्वारा स्थापित, यह क्लस्टर समुद्री अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों, शोधकताओं, निवेशकों और कंपनियों के सहयोगी केंद्र के रूप में कार्य करता है।

भारत ने रोम में चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया; 2027 में अगले संस्करण की मेजबानी के लिए बोली लगाई

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने इटली के रोम में 11-12 सितंबर, 2025 को आयोजित चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन (सीजीजीएस) में, वैश्विक समुद्री शासन को मजबूत करने और अधिक सुरक्षित स्वच्छ समुद्रों के को आकार देने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आईसीजी के महानिदेशक परमेश शिवमणि के नेतृत्व में दो सदस्यीय भारतीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने 'गार्जियंस अगेंस्ट द ब्लेजः आईसीजी टैक्टिकल रिस्पांस टू फायर इमर्जेंसीज' शीर्षक से एक व्याख्यान दिया, जिसमें समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने में भारत की विशेषज्ञता और रचनात्मक भूमिका को दशार्या गया। आईसीजी ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले पांचवें सीजीजीएस की अध्यक्षता के लिए बोली लगाने की इच्छा जताई है।

इस शिखर सम्मेलन में 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता इटली और जापान ने की और वैश्विक

महासागरीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर जोर दिया।

इस आयोजन ने समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री दुर्घटनाओं और समुद्री सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया में सर्वोत्तम विधियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। शिखर सम्मेलन के दौरान उन्नत तकनीकों, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने और समुद्री सुरक्षा के साझा लोकाचार के तहत अंतर-क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई।

जापान तटरक्षक बल और निप्पॉन फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2017 में पहली बार आयोजित, तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन संवाद और विश्वास-निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। इस शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने वर्चुअल माध्यम से समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, खोज और बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन में तटरक्षक बल के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।